

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 412]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 1970/कार्तिक 25, 1892

No. 412]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 1970/KARTIKA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 12th November 1970

S.O. 3759.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the management of the Oil and Natural Gas Commission, Dehra Dun and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is of opinion that the said dispute involves a question of national importance and that the dispute is also of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be affected by such dispute.

And whereas the Central Government is of opinion that the dispute should be adjudicated by a National Tribunal.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7B and sub-section (1A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes a National Industrial Tribunal at Delhi of which Shri Mahesh Chandra shall be the Presiding Officer and refers the said dispute to it for adjudication.

SCHEDULE

“What should be the amount, if any, of depreciation deductible under section 33A of the Payment of Bonus Act, 1965 as prior charge for the purposes of computation of available surplus.

(1829)

2. Whether the following amounts are allowable for computation of Gross Profits under the Payment of Bonus Act, 1965 and if allowable, to what extent?

(i) Depletion of Producing Property : Rs. 96,78,070 (net, after deducting depreciation); and

(ii) Amortisation of Development Expenditure in areas other than Producing Properties : Rs. 4,65,22,374 (net, after deducting depreciation).

3. What should be the amount, if any, of Development Rebate allowable as per Payment of Bonus Act, 1965 and its bearing on the payment of bonus for the year 1966-67.

4. Whether the interest at Rs. 1,01,49,188 on loans from the Government of India charged in the Profit and Loss Account is allowable for the computation of Gross Profits under the Payment of Bonus Act, 1965?

5. What should be the amount deductible as direct taxes in terms of section 6(c) of the Payment of Bonus Act, 1965 for arriving at the available surplus.

6. Whether the losses incurred by the Management on the fixed assets and written off as such in the Profit and Loss Account at Rs. 11,26,050 are deductible as an allowable expenditure for the purpose of arriving at the Gross Profits under the Payment of Bonus Act, 1965?

7. Whether the amount of Rs. 88,88,020 charged in the Profit and Loss Account as Provision for Doubtful Debts should be added back to the Profit in the computation of Gross Profits under the Payment of Bonus Act, 1965?

8. Whether the amount of Rs. 59,47,077 not included in the sale proceeds of the year pending arbitration but shown as a part of the note in the Profit and Loss Account or the net amount of Rs. 24,25,532 finally determined as payable by the Award should be added to the income of the year?

9. *Determination of net profit.*—Whether the provisions of the Companies Act are applicable for the determination of net profit? If so, to what extent and in which respect?

10. *Royalty.*—Whether the amount of Rs. 1,89,17,630/- covered in expenses of Rs. 4,52,55,499/- charged towards production expenditure in profit and loss account should be added back for computation of gross profit in view of the fact that the said amount is an expenditure on Royalties?

11. *Return on Capital.*—Whether the amount of Rs. 111.69 crores being funds advanced by the Government of India to ONGC for business under section 16 of the ONGC Act 1959, be deemed to be same as paid up capital as applicable to statutory corporations or as equity share Capital applicable in the case of Indian Companies Act?

12. Whether the prior deduction on the basis of 8½ per cent on such advances of the Government claimed by the Commission is admissible for the purpose of determination of available surplus under the Bonus Act? Or the capital of the Commission should stand on a different footing and return for the same worked out on the basis of the capital structure, whether there is no share capital as recommended by Bonus Commission?

13. *Transportation and Freight.*—Whether the expenditure under the head Transportation and Freight charged to profit and loss account which also include depreciation, is allowable as an expenditure under the payment of Bonus Act? If so, what should be the amount allowable in this respect, and what should be the principles for such deductions?

14. *Computation of Bonus for 1966-67.*—On the basis of the decisions on the points referred to above, what should be the Bonus payable to workers for the year 1966-67 as per the Bonus Act.

[No. 4/67/70-LR-IV.]

R. ANANDAKRISHNA, Jt. Secy.

भ्रम, रोजगार और पुनर्वसि मंत्रालय

(भ्रम और पुनर्वसि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 1970

का.अ. 3759—प्रतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में आयल एण्ड नैचुरल गैस कमिशन, देहरादून के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्व का एक प्रश्न अन्तर्गत है और कि विवाद इस स्वरूप का भी है कि इस से एक से अधिक राज्य में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों का प्रभावित होना सम्भाव्य है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि विवाद का न्यायनिर्णयन एक राष्ट्रीय अधिकारण द्वारा किया जाना चाहिए ।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख और धारा 10 की उपधारा 1क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली में एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री भूद्वेश चन्द्र होंगे और उक्त विवाद को हल न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“उपलब्ध बचत का हिसाब लगाने के लिये बोनस अदायगी अधिनियम 1965 की धारा 6(क) के अन्तर्गत पूर्ववर्ती प्रभार के रूप में कम करने योग्य मूल्यहास की, यदि कोई हो, कितनी राशि होनी चाहिए ।

2. क्या निम्नलिखित राशियां बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत समस्त लाभों का हिसाब लगाने के लिये स्वीकार्य हैं, यदि हैं, तो किस हद तक?

(i) उत्पादक सम्पत्ति का विहास : 96, 78, 070 रु० (कुल, मूल्य हास कम करने के पश्चात्) ; और

(ii) उत्पादक सम्पत्तियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी व्यय का परिशोधन : 4,65,22,374 रु० (कुल, मूल्यहास कम करने के पश्चात्) ।

3. बोनस अदायगी अधिनियम के अनुसार विकास-सम्बन्धी छूट की स्वीकार्य राशि, यदि कोई हो, कितनी होनी चाहिए और वर्ष 1966-67 के लिए बोनस की अदायगी से इस का क्या सम्बन्ध होना चाहिए ।

4. क्या बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कुल लाभों का हिसाब लगाने के लिये लाभ और हानि लेखों में, भारत सरकार से लिये गये ऋणों पर जिनकी राशि 1,01,49,188 रु० है, व्याज को लगाया गया खर्च स्वीकार्य है ?

5. बोनस अदायगी अधिनियम 1965 की धारा 6(ग) के अन्तर्गत उपलब्ध बचत आधारा

6. क्या प्रबन्धन द्वारा निम्नित सम्पदा में से उठाई गई हानियां जो लाभ और हानि लेख में हानियों के रूप में बड़े खाते डाली गई और जिन की राशि 11,26,050 रु० है, बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कुल लाभों को मालूम करने के लिए, एक स्वीकार्य खर्च के रूप में कम करने योग्य हैं ?

7. क्या बोनस अदायगी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत कुल लाभों का हिसाब लगाने के लिये जो लाभ और हानि लेख में सन्दिग्ध कर्जों के लिए व्यवस्था रखने हेतु 88,88,020 रु० की राशि का खर्च लगाया गया है, उसे लाभ में फिर से जोड़ देना चाहिए ?

8. क्या 59,47,077 रु० की राशि जो कि मध्यस्थ निर्णय प्राप्त होने तक वर्ष की बिक्री आय में शामिल नहीं की गई बल्कि लाभ और हानि लेख में टिप्पणी के एक भाग में बताई गई है या 24,25,532 रु० की शुद्ध राशि जो कि पंचाट द्वारा अन्ततः देय निर्णय की गई है, वर्ष की आमदनी में जोड़ देनी चाहिए ?

9. शुद्ध लाभ का निर्धारण:—क्या शुद्ध लाभ का निर्धारण करने के लिये कम्पनी अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं ? यदि होते हैं तो किस हद तक और किस बारे में ?

10. स्वामित्व :—क्या 1,89,17,630 रु० की राशि को जो कि 4,52,55,499 रु० की खर्चों की राशि में शामिल है, जिसे लाभ और हानि लेख में उत्पादन सम्बन्धी व्यय के रूप में खर्च दिखाया गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त राशि स्वामित्व सम्बन्धी व्यय है, कुल लाभ का हिसाब लगाने के लिये, फिर से जोड़ देना चाहिए ।

11. पूंजी का मुनाफा :—क्या श्री० एन० जी० सी० अधिनियम 1959 की धारा 16 के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा श्री० एन० जी० सी० को कारोबार के लिये दी गई 111.69 करोड़ रुपये की राशियां प्रदत्त पूंजी की तरह उसी प्रकार समझी जाएं जैसे कि सांविधिक निगमों के बारे में समझी जाती हैं या ईक्विटी शेयर पूंजी समझी जाएं जैसे कि भारतीय कम्पनी अधिनियम के बारे में लागू होती हैं ।

12. क्या सरकार द्वारा दी गई ऐसी राशियों पर साढ़े छठ प्रतिशत के आधार पर की गई पूर्ववर्ती कटौती करने का, जिनके लिये प्रायोग द्वारा बोनस अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध बचत निर्धारण करने के लिये, दावा किया गया है, स्वीकार्य है ? या प्रायोग की पूंजी एक मूल्य प्रकार की मानी जाये और उस पर मुनाफे का हिसाब पूंजी के ढांचे के आधार पर लगाना चाहिए । क्या बोनस प्रायोग की सिफारिश के अनुसार हिस्सा पूंजी नहीं है ?

13. परिवहन और बहन शुल्क :—क्या परिवहन और बहन शुल्क शीर्ष के अन्तर्गत व्यय, जिसे लाभ और हानि लेख में खर्च के रूप में लगाया गया है, और जिसे में मुख्यह्रास भी शामिल है, बोनस अदायगी अधिनियम के अधीन व्यय के रूप में स्वीकार्य है । यदि स्वीकार्य है तो इस बारे में कितनी राशि स्वीकार्य है और ऐसी कटौतियों के लिये क्या सिद्धान्त अपनाये जाने चाहिए ?

14. 1966-67 वर्ष के लिए बोनस का हिसाब :—ऊपर निर्दिष्ट विषयों पर निर्णयों के आधार पर, बोनस अधिनियम के अनुसार 1966-67 वर्ष के लिये कर्मकारों की कितना बोनस देय होना चाहिए ।

[संख्या 4/67/70—एच० और०-4]

भार० प्रगल्भाकरण, संवत्त संविदः ।